

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, HARYANA

Note for Pad

Socio-economic survey

On the directions of Ministry of Rural Development and NITI Ayog, the Rural Development Department had conducted the Socio-economic survey on the indicators fixed by the MoRD and NITI Ayog in 2010. Thereafter, no directions have been received from the Government of India. The information for Rural areas was collected digitally with the help of Bharat Electronic Limited (BEL) in their software. The data was then disclosed by the Govt. of India for using for various schemes in 2015-16.

In January 2019, the State Government launched an online application titled as 'BPL Entitlement' on e-Disha/SARAL portal for receiving applications in a specified format through VLEs/CSCs from general public who claimed to be included in BPL list. The online filled in information was verified by BDPO office, Gram Sachiv and concerned GPs. Thereafter, the report was forwarded to the DCs for district level committee for inclusion in the BPL list. The concerned DFSCs issued the ration cards to the finalised families. On 2.11.2020, the State Government decided to integrate the mechanism of BPL identification with Parivar Pehchan Patra (PPP) and till such time of its integration, the present portal(saral) for registration of BPL applications was closed.

Since then, the Socio-economic data is being looked after by the CRID for rural as well as urban areas for updation. The BPL cards are now prepared by the DFSC on the online data sent by the CRID directly.

Hence, there is no proposal under consideration with the Rural Development Department for conducting socio-economic survey in the Haryana State.

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा

नोट फार पेड

सामाजिक - आर्थिक सर्वेक्षण

ग्रामीण विकास मंत्रालय और नीति आयोग के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग ने 2010 में एमओआरडी और नीति आयोग द्वारा तय संकेतकों पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया था। इसके बाद भारत सरकार से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) की मदद से उनके सॉफ्टवेयर में डिजिटल रूप से एकत्र की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के उपयोग के लिए 2015-16 डेटा साक्षा किया गया था।

जनवरी 2019 में, राज्य सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल होने का दावा करने वाली आम जनता से वीएलई/सीएससी के माध्यम से एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने के लिए ई-दिशा/सरल पोर्टल पर 'बीपीएल एनटाईटलमेंट' नामक एक ऑनलाइन एप्लिकेशन लॉन्च किया। ऑनलाइन भरी गई जानकारी को बीडीपीओ कार्यालय, ग्राम सचिव और संबंधित जीपी द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके बाद बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए जिला स्तरीय समिति के लिए रिपोर्ट डीसी को भेजी गई। संबंधित डीएफएससी ने अंतिम रूप से चयनित परिवारों को राशन कार्ड जारी किए। 2.11.2020 को, राज्य सरकार ने बीपीएल पहचान के तंत्र को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया और इसके एकीकरण के समय तक, बीपीएल आवेदनों के पंजीकरण के लिए वर्तमान पोर्टल (सरल) को बंद किया गया।

तब से, सीआरआईडी द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक डेटा को अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। बीपीएल कार्ड अब डीएफएससी द्वारा सीधे सीआरआईडी द्वारा भेजे गए ऑनलाइन डेटा पर तैयार किए जाते हैं।

इसलिए, हरियाणा राज्य में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।